अभी भी उनके पास नार्म्स हैं लेकिन इसका मिसमैनेजमैंट हुआ है। यह तो हो गया लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं? यही बोलते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे, इनक्वायरी करेंगे। आप या तो टाइम बाउंड कर दीजिए कि दो महीने या छः महीने मैं कुछ हो जाएगा या फिर आप रुपया देते रहेंगे, कम्पनियों का कुछ नहीं होगा। आप हमें अपना प्रोग्राम बता दीजिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: अभी बी॰आई॰एफ॰आर॰ में है, उसका फैसला होना है। इसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। पहले क्या बता सकते हैं? गवर्नमेंट ने एक ही कम्पनी को अपने खजाने से 119 करोड़ से अधिक रुपया दिया है, लेकिन फिर भी वह नहीं चली।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला: सभापति महोदय, मैं अपने प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस कंपनी में कोई ऐसी घटना भी हुई थी जिसमें यहां के एम.डी. (मैनेजिंग डायरेक्टर) पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था और अब इस हमले के बाद कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं है? जिन लोगों ने हमला किया था उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति महोदय, मेरी नोलेज में ऐसी कोई घटना नहीं आई है लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो मैं उसकी इनक्वायरी करा लूंगा।

DR. A.R. KIDWAI: Mr. Chairman, Sir, today, in India, after the software industry, it is the pharmaceutical industry which is the most profitable business. Not only these two firms but also the IDPL, which was set up with great expectations, have totally failed. I would like to know from the, hon. Minister whether he would consider appointing a Parliamentary Committee to inquire into the matter.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: इस सजेशन पर विचार किया जा सकता है और मैं इसे देख लूंगा।

Assistance to Gujarat under Non-Formal Education Programme

*184. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the assistance provided to Gujarat under Non-Formal Education Programme during the last two years, year-wise;

(b) the amount spent thereon,year-wise;

(c) the number of persons made literate through this programme by providing funds to State Government and voluntary agencies; and

(d) the lapses found in utilisation of funds and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN): (a) to (c) Non-Formal Education (NFE) programme was implemented in Gujarat through 1685 centres under 19 Voluntary Agencies. The number of beneficiaries in each centre is approximately 25. Rs. 124.00 lakhs was provided during 1998-99 and Rs. 65.57 lakhs in 1999-2000 for implementation of the programme. In addition 100 NFE centres were run by the Surat Municipal Corporation upto 31.5.1998 for which Rs. 7.48 lakhs were sanctioned in 1998- 99.

(d) No lapses in utilisation of funds have come to the notice of this Department. However, in the case of one organisation namely, Shramik Vidyapeeth, Vadodara, some funds were temporarily withdrawn by the Director of the organisation for her personal use. However, the funds were deposited back in the organisation's account with interest and thereafter the amount was utilised in accordance with the project provisions. An Administrator has been appointed for the Vidyapeeth and a new Board of Management has been constituted which will decide further action regarding the Director.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Mr. Chairman, Sir, in the reply, the hon. Minister has stated that the number of beneficiaries in each centre is approximately 25. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has fixed up any target that so many persons will be made literate, whether any monitoring agency is there to see whether the work is properly carried out or not, and whether under Non-Formal Education Programme any amount was provided to the Gujarat Government.

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति महोदय, एप्रोक्सिमेटली इसलिए कहा क्योंकि यह नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन शिक्षा तो सभी को देनी है। यह नॉन फॉर्मल एजुकेशन से फॉर्मल एजुकेशन को सप्लीमेंट्री देना है इसीलिए इसे एप्रोक्सिमेटली कहा गया। साधारणतया एक केन्द्र में पच्चीस विद्यार्थी हैं। हमारे पास जितनी आवश्यकताएं आती हैं उतने ही केन्द्र खोलने की अनुमति और पैसा भी दिया जाता है।

दूसरा प्रश्न जो इनके द्वारा पूछा गया है, उस संदर्भ में मैं बताना चाहती हूं कि गुजरात सरकार को नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता था, चूंकि अब गुजरात सरकार ने पूरे तौर पर अलग से पूर्ण लिटरेसी का प्रयास शुरू कर दिया है इसलिए नॉन फार्मल एजूकेशन का पैसा धीरे-धीरे घटाकर अब केवल स्वैच्छिक संस्थाओं को दिया जा रहा है। जिसका विवरण में आपको दे रही हूं। 1998-99 में गुजरात में 1,785 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को संचालित करने के लिए नीतियां जारी की गई थीं। उसमें 19 स्वैच्छिक एजेंसियों का मैंने उत्तर में भी बताया है, उसमें जारी

किया गया था। 19 स्वैच्छिक एजेंसियों के द्वारा संचालित 1685 केन्द्र हैं। इसमें राज्य क्षेत्र के 100 केन्द्र भी शामिल हैं। लेकिन अब गुजरात राज्य सरकार एक प्रकार से नॉन फार्मल एजुकेशन के लिए पैसा नहीं लेती।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: My second supplementary is that the amount in 1999-2000 is reduced, and what the reason is for the reduction? I would also like to know whether the voluntary agencies were not able to spend the money or the Government could not give more money.

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति महोदय, पैसा किसी भी प्रकार से रिड्यूस नहीं किया गया है। बात यह है कि जैसे भी कंपलायंस रिपोर्ट आती है, आगे का पैसा दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा है कि जितनी भी डिमांड आती है, उतना पैसा दिया जा रहा है। लेकिन कंपलायंस रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का पैसा दिया जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से पैसा कम नहीं किया गया है।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति महोदय, माननीया मंत्री महोदया की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें 42000 केन्द्रों में नॉन फार्मल एजुकेशन लोगों को दी जाती है और 124 लाख रुपया उनको दिया गया है। मेरा सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इतना पैसा दे रही है और बड़ोदा में घपला भी हुआ, उसकी इनक्वायरी हुई और नया बोर्ड ऑफ मेनेजमेंट डिसिज़न लेगा। डायरेक्टर ने पैसा विदड्रा कर लिया था जब आपने ऐक्शन लिया तो फिर पैसा जमा करवा दिया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप किस तरीके से इसकी सारी मोनिटेरिंग करते हैं? 19 वालेंटरी एजेंसीज़ काम कर रही है गुजरात में। नॉन फार्मल एजुकेशन का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको इकट्ठा कर के कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी वालेंटरी एजेंसीज़ गई हैं और यह प्रोपर्ली काम कर रही हैं ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास मोनिटेरिंग के माध्यम से आई है या नहीं और यदि नहीं आई है तो आप इसके बारे में क्या मोनिटेरिंग करने जा रही हैं, यह बताइये?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी, इसकी इवेल्युएशन के लिए ज्वाइंट इवेल्युएशन टीम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ((**व्यवधान**)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूछ रहा हूं क्योंकि यहां से इतना पैसा देते हैं।

श्री सभापति: वह इवेल्यूएशन टीम की बात कर रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: आपने पहले इवेल्यूएशन की बात पूछी है। इसका मोनिटेरिंग यहां से किया जाता है। मैं वही बता रही हूं कि मोनिटेरिंग के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों मिल कर के एक ज्वाइंट टीम तैयार होती है और वह यहां से रिपोर्ट ले कर भेजती है। प्रत्येक राज्य सरकार को इस प्रकार

के हमारे पत्र भी गये है इस प्रकार की टीम तैयार कर के पूरे का पूरा इवेल्युएशन आना चाहिये जहां तक आपने गुजरात की बात पूछी है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यहा नॉन फार्मल एजुकेशन का पैसा जाता है, ऐसा नहीं है। हालांकि यह बात भी सही है कि एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन स्लम्स में भी जो ऐसे बच्चे रहते है, कई शहरों में स्लम्स है जहां पर वह बच्चे कुछ देर बाद स्कूल जाना छोड़ देते है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका फार्मल एजुकेशन में हिस्सा नहीं रहता है, रोज़ स्कूल में नहीं जाते है, उनके लिए भी यह केन्द्र चलाए जाते है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह काम हो रहा है। गुजरात में 19 एजेंसियां है, इसकी डिटेल में आपको दे दूंगी। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगी कि उसमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियां भी हैं।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, नॉन फार्मल एजुकेशन का पूरा कार्यक्रम ऐसा है (व्यवधान)

श्री सभापति: सवाल गुजरात का है।

श्री मूल चन्द मीणा: गुजरात का है, लेकिन यह कार्यक्रम ऐसा है जो केवल कागज़ों पर चल रहा है सारे देश के अन्दर। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह सवाल गुजरात पर है।

श्री मूल चन्द मीणा: गुजरात हो, राजस्थान हो, मैं मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं। यह कार्य कार्यक्रम कागजों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, वह वेस्टेज है, यह देखा जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम की समीक्षा के लिए क्या आप संसदीय कमेटी से समीक्षा कराएंगे या कोई हाई पावर कमेटी बना कर उसकी समीक्षा कराएंगे? फर्जी कार्यक्रम चल रहे है। फ़र्जी कार्यक्रमों से रिपोर्टें आ रही हैं और काग़ज़ों पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह राजस्थान में देखने को मिलता है।

श्री सभापति: ठीक है हो गया।

श्री मूल चन्द मीणा: मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कोई हाई पावर कमेटी से इसकी समीक्षा कराएंगी कि वास्तव में यह कार्यक्रम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या काग़ज़ों पर ही चल रहा है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति महोदय, यह बात आपने जो कही है मुझे थोड़ा दुख होता है क्योंकि नान फार्मल एजूकेशन में हम यह तो नहीं कह सकते है कि एक एक बात को लेकर एक एक लड़का, लड़की कितना पढ़े। लेकिन साधारणतया जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते है उनको कुछ शिक्षा मिले, उसमें इनोवेटिव शिक्षा भी सम्मिलित है यह मिले, इस प्रकार की यह स्कीम है। लेकिन अब यह बात की गयी है कि यह जो स्कीम पूरी थी–नान फार्मल एजूकेशन स्कीम, यह जैसे

कि हमारे वित्त मंत्री ने गए बजट में डिक्लेयर किया था कि एक सर्वशिक्षा अभियान करके जो प्रणाली प्रारंभ कर रहे हैं इसमें आने वाले सालों में अब यह स्कीम बंद करके नान फारमल एजूकेशन की- क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसमें कुछ सुझाव दिए हुए हैं, अपनी भी एक इस प्रकार की जो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन देखने वाली कमेटी है उन्होंने भी सुझाव दिया-तो अब यह पूरी योजना जो है यह एजूकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत आ जाएगी तथा राज्यों के द्वारा चलायी जाएगी। पैसा राज्यों को दिया जाएगा और राज्य अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने जिलों में, जिले से पूरी स्कीम भेजेंगे। राज्यों को अब यह पैसा दिया जाएगा ताकि उसका पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन भी राज्य कर सकें। इस प्रकार की आने वाली दिनों में व्यवस्था कर रहे हैं। तो आने वाले बजट से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी इस एजूकेशन गारंटी स्कीम में।

श्री लेखराज बचानी: चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो 'बी' एण्ड 'सी' में है, 'बी' मे लिखा है:-

Part (b) says, "The amount spent thereon, year-wise;" There is no reply to this question. Part (c) says, "The number of persons made literate through this programme." The Minister has not given the details. She has given only the provision of funds. She has also given the approximate number of beneficiaries. But the did not give details of the number of beneficiaries. Thirdly, I want to know: What is the time-frame fixed for this programme? I would like to know whether the programme, as expected, has benefited the real beneficiaries.

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी, गुजरात में 1998-99 और 1999-2000 के दौरान यह जो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चला उसमें करीब-करीब 50 हजार लोग लाभान्वित हुए हैं। 50 हजार में 40 हजार जो हैं ये स्वैच्छिक क्षेत्र के लोगों द्वारा जो सोशल आर्गेनाइजेशंस, संस्थाओं ने केन्द्र चलाए थे, उनके द्वारा हैं और 10 हजार जो राज्यों के द्वारा केन्द्र चलाए जा रहे थे उसमें लाभान्वित हुए हैं। उसमें जैसे शुरू में ही हमने कहा था कि इसमें जो पैसा दिया गया है साधारणतया 124 लाख है और यह पैसा कितना दिया है उसको भी मैंने उत्तर में दिया हुआ है।

जो टाइम पीरियड की बात की जा रही है इसमें साधारणतया ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहता है। एक-एक साल की ऐसी ये स्कीमें रहती हैं। लेकिन एक साल ही नहीं, जब से स्कीम आती है तब से वह बात शुरू हो जाती है और इसलिए time period varies according to the programme, according to the age, according to the number of children. तो ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड इसमें नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से स्कीम आती है, एक साल की दो साल की उसके अनुसार वह चलता है। जब तक वह स्कूल में जाए-ऐसी भी एक योजना चल रही है कि बच्चा स्कूल में जाना शुरू करे, इस नान फारमल से

फारमल स्कूल में, फारमल स्कूलिंग से जुड़े। इस प्रकार की यह स्कीम है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि इतना टाइम पीरियड इस संस्था का है। संस्थावाइज बताएं तो जब कार्यक्रम शुरू होता है, वहां से उनका टाइम शुरू होता है।

MR. CHAIRMAN: Mr. Faleiro. This is a question about Gujarat.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Faleiro, every Member is required to speak from his seat.

SHRI EDUARDO FALEIRO: I am sorry, Sir. I am going to my seat. Thank you, Sir.

Regarding the curriculum for non-formal education and also for formal education in Gujarat and other States, on the 14th November, that is, just two weeks ago, your senior colleague, the hon. Minister, released the National Curriculam for Education. He called it 'national'. For the first time in the history of...

MR. CHAIRMAN: The question is regarding Gujarat.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Yes, Sir. It is for the first time in the history of this country that this curriculum has been released without consulting the State Government, whether of Gujarat or of any other State. What steps has the Minister or the Government taken to consult the State Government and to call a meeting of the Central Advisory Board on Education for this purpose, to approve this?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी, एक तो यह करीकुलम से संबंधित है। अनौपचारिक शिक्षा जो रहती है उसमें केवल इतनी बात रहती है कि जो बच्चा स्कूल से बाहर है वह स्कूल से कैसे जुड़े। उसके लिए यह पूरी शिक्षा गारंटी योजना बनाई गई है, जैसा कि मैंने कहा है और करीकुलम की जहां तक बात है तो जो नीति बनाई गई है वह सभी राज्यों को भी भेजी गई है और स्टेट्स कंसल्टेशन चालू है। लेकिन उसका मुझे लगता है कि इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सूरत शहर को यहां पर खास तौर से अंकित किया है, क्योंकि उस समय मैं सूरत शहर की मेयर थी और 1998-99 में हमने जो इस विषय पर काम किया उसके लिए एक तरह से इन्होंने हमारी प्रशंसा की है। अब मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगी कि उन्होंने 1998-99 में 7 लाख 48 हजार रुपये जो स्वीकृत किए थे लेकिन वर्ष 2000-2001 में क्या और अधिक धनराशि स्वीकृत करने की कोशिश करेंगी ताकि हम अपने सूरत शहर में और अधिक

काम कर सकें? दूसरा मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसा प्रावधान उन्होंने दूसरे शहरों के लिए भी किया है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि आने वाले साल में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन योजना जो है यह एक प्रकार से एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत है, इसलिए इसमें अब और नई स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है। जो पहले से स्वीकृत कार्यक्रम हैं उन्हीं कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा और उसके बाद यह पूरा का पूरा कार्यक्रम एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत आ जाएगा और राज्यों के द्वारा जो-जो बातें आयेंगी या राज्य जो कुछ भी भेजेंगे उसके अनुरूप ही इस पर स्वीकृति दी जाएगी। यह राज्यों में एक प्रकार से दिया गया है। माननीय सभापति जी, सूरत का कार्यक्रम अब बंद हो गया है।

Renewal of Bookstall Contracts

*185. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2898, given in the Rajya Sabha on the 18th August, 2000 and state:

(a) whther it is a fact that no discrimination of any kind is allowed between the same type of trade, under Article 19(i) G of the Constitution of India;

(b) if so, the reasons for not renewing all the bookstall contracts for a period of nine years and for withdrawing the sole selling clause, excepting the A.H. Wheeler and Co.;

(c) whether Government have received a number of suggestions from M.P's for removing all the discriminations between A.H. Wheeler and Company and the other bookstall contractors on all the Indian Railways; and

(d) if so, the details of action taken thereon?

THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Prior to 1960, M/s A.H. Wheeler & Co. had a monopoly in operating bookstalls on the entire railway system except Southern Railway and a part of South-Central Railway, where M/s. Higginbothams Ltd. had their bookstalls. In 1960 their monopoly rights were restricted to only those stations where M/s A.H. Wheeler & Co. were having bookstalls and their term of licence was kept for 5 years.